ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज व्यवस्था (समस्याऐं एवं सुझाव)

* डॉ. मनीष दुबे

प्रस्तावना

वैष्वीकरण के इस युग में हर क्षेत्र में विकास चाहे ग्रामीण हो या शहरी आवष्यक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को दो बड़े भागों में बांटा गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं शहरी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित है या कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यवसायों पर आधारित है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। एवं वहीं पर अर्थोपार्जन करता है। अतः यह कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पूर्णतः ग्रामीण विकास पर आधारित है अतिषयोक्ति नहीं होगी। ग्रामीण विकास की कल्पना के बगैर राष्ट्र की प्रगति का स्वप्न अपूर्ण रहेगा।

पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण समाज की रीढ़ है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने एवं ग्रामों का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं नियमन, क्रियान्वयन आदि के लिए ही पंचायत राज की स्थापना की गई। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देष्य जनभागीदारी को ग्राम विकास के लिए उपयोग लाना ग्रामों की मूलभूत समस्याओं को हल करना और ग्रामीण क्षेत्रों में, अधोसंरचना, रोजगार, सामाजिक न्याय आदि की स्थापना करना है। वर्तमान में भारत के गांव, ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्य धारा में अग्रणी भूमिका निभा रहे है।.

* डॉ. मनीष दुबे, **सहायक प्राध्यापक, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर,** dubey.manish519@gmail.com

I. शोध–प्रविधि

प्रस्तुत आलेख की रचना हेतु अध्ययन सामग्री का संकलन प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्य से किया गया है। उक्त साक्षात्कार ग्राम पंचायत के अधिकारियों, हिताधिकारियों एवं ग्राम सभा के सदस्यों से लिया गया है। विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से उपलब्ध जानकारियों को भी इस शोध में समाहित किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु 250 ग्रामवासियों से साक्षात्कार लिया गया है।

II. शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देष्य ग्रामीण विकास में पंचायता एवं उनसे जुड़े पक्षों को योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना एवं इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

III. ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों का महत्व

ग्रामीण विकास हेतु पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं एवं लोकतांत्रिक प्रणाली से इनके गठन की व्यवस्था की गई है ताकि वे विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर सके यही कारण है कि ग्राम पंचायतों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। पंचायतों का महत्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है –

1)पंचायतें सामाजिक सुधारों को गति देने का कार्य करती है।

2)पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का अधोसंरचनात्मक विकास सम्भव हुआ है।

3)पंचायतें लोगों में सामुदायिक चिंतन, सहयोग व सहकारिता को बढ़ावा देती ह।

4)इनके लोगों को विभिन्न विकास व प्रषासनिक गतिविधियों में सहभागिता का अवसर मिलता है।

5)इनकी प्रभावषीलता से जन समस्याओं का त्वरित निदान सम्भव है।

6)शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास पंचायतों के माध्यम से सम्भव हो सका।

7)विभिन्न रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा आदि का संचालन पंचायतें बेहतर ढंग से कर रही है।रू

IV. शोध विश्लेषण

शोध के दौरान 250 ग्राम वासियों से साक्षात्कार किया गया जिनके बीच ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ लेने की स्थिति का आकलन किया गया जो निम्न तालिका से स्पष्ट है –

तालिका क्र. 1

क्या आप किसी योजना से जो कि ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित है, के लिये आवेदन करने पर लाभान्वित हुए हैं।	हाँ	नहीं
कुल ग्रामवासियों की संख्या 250	169	81

स्तोत्र व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका क्र. 1 स स्पष्ट है कि 200 में से 169 अर्थात् 68ः ग्रामवासी ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं वहीं 32 प्रतिषत ग्रामवासी ऐसे हैं जो इन योजनाओं के लाभ से आज तक वंचित हैं।

जिन हितग्राहियों को ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाआ का लाभ प्राप्त हुआ उनसे इन योजनाओं में लाभ लेने में आने वाली समस्याओं की स्थिति जानने का प्रयास किया जो इस प्रकार है –

तालिका क्र. 2

योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किन कठिनाईयों का सामना किया	कोई समस्या नहीं	भ्रष्टाचार	प्रक्रिया का जटिल होना	लाभ मिलने में समय अधिक लगना	अन्य कारण
कुल संख्या 169	21	28	51	49	20

स्तोत्र व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 13ः हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया है। 17ः हितग्राही ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा होना दर्षाते हैं। 30ः हितग्राहियों ने आवेदन की प्रक्रिया का जटिल होना और 29ः हितग्राहियों ने प्रकरण के निराकरण में विलम्बन को इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्या दर्षाया है। 11ः हितग्राही अपूर्ण जानकारी, मध्यस्थों एवं एजेन्टों का हस्तक्षेप आदि इन योजनाओं की समस्या दर्षाते हैं।

ऐसे ग्रामीण जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हित प्राप्त करने हेतु आवेदन किया परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका इसका मूल कारण वे क्या मानते हैं यह निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्र. 3

आवेदन के पश्चात् भी लाभ नहीं मिल सका	पात्र नहीं थे	भ्रष्टाचार के कारण	योजना की पूर्ण जानकारी नहीं थी	उचित मध्यस्थ का नहीं मिलना	अषिक्षा	अन्य

इसका कारण है कि						
कुल संख्या 81	31	8	11	11	13	07
	38ण्3:	10:	13ण्5:	13ण्5:	16:	8ण्7:

स्तोत्र व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 38ण्3: लोगों को योजनाओं का लाभ इसलिये नहीं मिल सका क्योंकि वे अपात्र थे वहीं 10: लोग भ्रष्टाचार 13ण्5: योजनाओं की अपूर्ण जानकारी, 13ण्5: ग्रामीण मध्यस्थों की कमी 16:, अषिक्षा एवं 8ण्7: अन्य कारणों से ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले सके।

V. पंचायतों को योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याऐं

शोध के दौरान ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं अन्य पक्षों से ऐसे तथ्य प्राप्त हुए जिनसे ग्राम पंचायतों को अपनी योजनाओं का संचालन करने में बाधा प्रतीत होती है। इन बाधाओं एवं समस्याओं के कारण ग्राम पंचायतें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाती हैं ये समस्याऐं निम्नलिखित हैं :–

1)पंचायत जनप्रतिनिधियों को पंचायतों के प्रावधानों की अपूर्ण जानकारी होने से वे अधिकारियों के समक्ष सही–गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं एवं पंचायतों का संचालन अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों (षा. अधिकारियों) द्वारा किया जाता है।

2)ग्राम सभाओं की अनियमित बैठकें एवं इन बैठकों में सदस्यों का रूचि नहीं लेना।

3)दलगत राजनीति एवं भाई–भतीजावाद पंचायत राज के सामने एक बड़ी चुनौती है।

4)भ्रष्टाचार एवं मध्यस्थों की उपलब्धता सही लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने देते हैं।

5)ग्रामीणों की अषिक्षा एवं जागरूकता में कमी आज भी ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है।

6)ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाऐं संचालित की जा रही है उनका उचित प्रचार–प्रसार नहीं किया जाता है।

7)हितग्राही योजनाओं के अन्तर्गत जो राषियां दी जाती है वो अपर्याप्त हैं इन अनुदान राषियों को बढ़ाना चाहिए।

8)हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है।

9)हितग्राही येाजनाओं मे प्रकरणों का निराकरण होने में समय अधिक लगता है।

VI. महत्वपूर्ण सुझाव

शोध के दौरान समस्याओं का अध्ययन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो निष्चित ही ग्राम पंचायतों को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

1)जन साक्षरता को प्रोत्साहन देना चाहिए।

2)ग्राम सभा को सषक्त बनाना चाहिए इसकी बैठकों का नियमितिकरण करना चाहिए।

3)शासकीय कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने की आवष्यकता है।

4)योजनाओं का प्रभावी प्रचार–प्रसार सुनिष्चित करना चाहिए।

5)जन पतिनिधियों का प्रषिक्षण षिविर आदि लगाकर उन्हें प्रषिक्षित करना चाहिए।

6)आवेदन प्रक्रिया को सरल करना चाहिए।

7)प्रकरणों के निराकरण की समयसीमा तय की जाए एवं इसका सख्ती से पालन किया जाए।

8)पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कठोर कदम उठाए जान चाहिए।

9)ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।

10)योजनाओं एवं पंचायतों के कार्यों की निरीक्षण व्यवस्था कठोर होनी चाहिए।

VII. निष्कर्ष

पंचायत राज का मूल उद्देष्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामों को सषक्त करना है। पंचवर्षीय योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके इसलिए पंचायतें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। किसी भी कार्य में समस्याऐं आना सहज बात है यही चुनौतियां पंचायतों के सामने भी है परंतु उचित नियमन एवं नियंत्रण से इन चुनौतियों का सामना कर पंचायतें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है।

पंचायती राज व्यवस्था प्रजातन्त्र की सूक्ष्मतम इकाई है। विकास पथ पर राष्ट्र को अग्रसर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण से ग्रामीण विकास की दिषा को एक नई प्रगति मिली है एवं ग्रामों का स्वावलंबन हुआ है।

सन्दर्भ

ग्राम पंचायतों की आवष्यकता एवं महत्व, साहित्य भवन पब्लिकेषन

भारतीय अर्थव्यवस्था, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

दैनिक भास्कर, नईदुनिया, फ्रीप्रेस

www.panchayat.com